इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 06 जनवरी 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

संस्थान की ओर से अपने सभी पाठकों को अत्यधिक सुखद एवं समृद्ध नव-वर्ष (2011) की शुभकामनाएं

विषय-सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
विदेशी मुद्रा विनिमय----------4
सहकारी बैंक----------4
अर्थव्यवस्था----------5
पारस्परिक निधियां----------5
सूक्ष्मवित्त ----------5
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------6
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
पूंजी बाज़ार----------6
पण्य (जिंस) बाज़ार----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत समीक्षा : दिसम्बर, 2010

क) मौद्रिक उपाय

1.भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद (रेपो) दर को 6.25% पर और प्रत्यावती पुनर्खरीद (reverse repo) दर को 5.25% पर बनाए रखना; आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) को अनुसूचित बैंकों की निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 6% पर बनाए रखना।

ख) चलनिधि सम्बन्धी उपाय

1.18 दिसम्बर, 2010 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) को उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 25% से घटा कर 24% करना।

2. आगामी एक माह में कुल 48, 000 करोड़ रुपये की रकम की सरकारी प्रतिभूतियां (G-secs) खरीदने हेतु खुले बाज़ार के परिचालन (OMO) की नीलामी करना। इन दोनों उपायों से चलनिधि में स्थायी आधार पर बढ़ोत्तरी होने की आशा है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात में निवल मांग एवं देयताओं के 1% की स्थायी कटौती को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 29 नवम्बर, 2010 को घोषित चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत अतिरिक्त चलनिधि सहायता अब 18 दिसम्बर, 2010 से 28 जनवरी, 2011 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के (2% की बजाय) 1% तक उपलब्ध है।

अप्रैल 2010 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम

- 21 अप्रैल : पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ा कर 5.25% कर दी गई। प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ कर 3.75% हो गई, आरक्षित नकदी निधि अनुपात 25 आधार अंक बढ़ कर 6% हो गया।

- 2 जुलाई : पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ा कर 5.50% कर दी गई। प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ कर 4% हो गई। प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद का 2रा सेट, पुनर्खरीद टेण्डर 16 जुलाई तक विस्तारित। बैंकों को निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.5% तक की अतिरिक्त चलनिधि सहायता। बैंक 16 जुलाई तक सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी पर दंडस्वरूप ब्याज में माफी की मांग कर सकते हैं।

- 27 जुलाई : पहली तिमाही समीक्षा; पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ा कर 5.75% कर दी गई, प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दर 50 आधार अंक बढ़ा कर 4.50% कर दी गई।

- 16 सितम्बर : मध्य तिमाही नीतिगत समीक्षा : पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ा कर 6% की गई । प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दर 50 आधार अंक बढ़ा कर 5% की गई।

- 2 नवम्बर : 2री तिमाही की समीक्षा : पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ा कर 6.25% की गई । प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ा कर 5.25% की गई।

- 9 नवम्बर : विशेष चलनिधि समायोजन सुविधा 16 दिसम्बर तक । बैंक निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 1% तक की अतिरिक्त चलनिधि समायोजन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बैंक 9 से 16 दिसम्बर तक सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी पर दंडस्वरूप ब्याज में माफी की मांग कर सकते हैं।

- 29 नवम्बर : विशेष चलनिधि समायोजन सुविधा 28 जनवरी तक विस्तारित। अतिरिक्त चलनिधि सुविधा बढ़ा कर बैंकों की निवल मांग एवं सावधि देयताओं की 2% कर दी गई। बैंक सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी पर दंडस्वरूप ब्याज में माफी की मांग पाक्षिक आधार पर कर सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में सांविधिक चलनिधि अनुपात 100 आधार अंक घटा कर 24% किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में जमाराशियों के एक अंश को सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी एवं सोने के रूप में रखने हेतु उधारदाताओं के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात सम्बन्धी अपेक्षा में 1 प्रतिशत की कटौती करते हुए उसे 24% कर दिया है। यह कार्रवाई प्रणाली में और अधिक चलनिधि लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों के एक अंग के रूप में बैंकों की हाल ही की मौद्रिक समीक्षा में घोषित इसी प्रकार की कटौती के अनुरूप है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में सांविधिक चलनिधि अनुपात उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 25% से घटा कर 18 दिसम्बर से 24% कर दिया गया है। इस नये उपाय का निहितार्थ यह है कि अब क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक निवेशगत प्रतिभूतियां कमतर और ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए अधिक उधार देने योग्य संसाधन रख सकते है।

मुख्य घटनाएं

खाता खोलने हेतु 'आधार' पर निर्भर करें

वित्त मंत्रालय ने बैंक खाते खोलने के लिए भारतीय अभिनव पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी आधार संख्या को एक आधिकारिक वैध प्रलेख के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस मुहिम से अब तक अपवर्जित लोगों को उनकी पहचान को सरलतापूर्वक साबित करने में उन्हें समर्थ बनाते हुए वित्तीय समावेशन में बढ़ोत्तरी होने की आशा है। भारतीय अभिनव पहचान प्राधिकरण सहभागी बैंकों के माध्यम से आधार में नामांकन के समय निवासियों के बैंक खाते खोलने के कार्य को सुगम बना रहा है, जिसके दौरान अपने ग्राहक को जानिए प्रक्रिया में एक वैध प्रलेख के रूप में 'आधार' की स्वीकार्यता इस प्रक्रिया को अड़चन-रहित बनाएगी।

नये युग के छोटे (piggy) बैंक

निजी बैंकों के लिए बच्चे संकेन्द्रण के नये समूह बन गए हैं। रंग-बिरंगे डेबिट कार्डों और फास्ट-फूड नुक्कड़ों से लेकर नर्सरी स्कूलों के विशेष सत्रों में छूटों तक निजी क्षेत्र के बैंक अलबत्ता कई प्रकार के सुरक्षोपायों के साथ बच्चों के बीच बचत खातों की श्रमसाध्य बिक्री कर रहे हैं। सशक्तीकरण के एक साधन और वित्तीय आयोजना एवं स्वाधीनता से जीवन के प्रारंभिक दौर में ही परिचय के रूप में डेबिट कार्ड माता-पिता को एटीएम से आहरणों तथा बिक्री केन्द्रों PoS) से खरीदारी की मासिक सीमाएं निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है। माता-पिता को एटीएमों के मामले में 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक और बिक्री केन्द्रों के मामले में 1000 रुपये से 5,000 रुपये तक की व्यय-सीमाओं वाले तीन विकल्प प्राप्त होते हैं। इस खाते के लिए निर्धारित तिमाही औसत शेषराशि 2,500 रुपये है। डेबिट कार्ड में पुस्तकें, खिलौने, फास्ट फूड और बच्चों को खुश करने वाली इसी प्रकार की कई एक खरीदियों के प्रस्ताव शामिल हैं।

आकांक्षी बैंकरों के लिए अखिल भारतीय आधार पर समान परीक्षा

आकांक्षी बैंकरों को प्रत्येक भतीकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए अलग-अलग परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं होगी। हजारों बैंकिंग व्यावसायिकों की बढ़ती आवश्यकता नें इन बैंकों को एक साथ आ मिलने और अखिल भारतीय आधार पर समान परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाने पर विवश कर दिया है। इस समान परीक्षा, जिसका संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा किया जाएगा, को उत्तीर्ण कर लेने पर अभ्यर्थियों को केवल साक्षात्कार के लिए उपस्थित रहने हेतु अलग-अलग बैंकों के विज्ञापनों का प्रत्युत्तर देना होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंक इस संयुक्त प्रयास में सहभागी होंगे, जो उन्हें ऐसे अभ्यर्थियों के समूह का उपयोग करने में समर्थ बनाएगा, जिन्होंने भर्ती के लिए समान परीक्षा में सफलता हासिल कर रखी है। जहां लिपिकीय संवर्ग के लिए अखिल भारतीय आधार वाली समान परीक्षा वर्ष में चार बार आयोजित की जाएगी, वहीं परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए यह दो बार आयोजित होगी। सफल अभ्यर्थियों को जारी किए गए अंकपत्र के 1 से 1.5 वर्ष तक वैध रहने की संभावना है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बैंकों से नकदी जमा प्रभार अधिकतम 5 रुपये रखने हेतु कहा गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से मूलेतर शाखा (जिसमें ग्राहक ने खाता खोल रखा है, उस शाखा को छोड़कर किसी अन्य शाखा) में जमा की जाने वाली किसी भी नकदी जमा पर 5 रुपये से अधिक नहीं प्रभारित करने के लिए कहा है। कुछेक बैंक इस प्रकार की जमा के लिए 110 रुपये जितनी भारी रकम प्रभारित करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गृह ऋण की अधिकतम सीमा तय

भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य के अनुरूप ऋण (लोन टू वैल्यू) की अधिकतम विनियामक सीमा निर्धारित किए जाने के परिणामस्वरूप अधिकांश उधारकर्ता अब मकान के मूल्य के 80 % तक बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के मामले में (20 लाख रुपये तक के आवास ऋण) मूल्य के अनुरूप अनुपात बढ़ कर 90% हो सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने काउंटर पर क्रय-विक्रय वाली विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों, पण्य मूल्य एवं मालभाड़ा जोखिमों की विदेशी बचाव व्यवस्था (hedging) की शुरूआत की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह ऐसे उत्पादों का प्रवर्तन किया है, जो काउंटर पर लेनदेन वाली विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी, पण्य बाज़ारों के सहभागियों तथा मालभाड़े में एक्सपोजर वाले व्यक्तियों को उनके मुद्रा जोखिमों को प्रतिरक्षित करने की सुविधा प्रदान करेंगे। नये दिशानिर्देश 1 फरवरी, 2011 से प्रभावी होंगे। ये छह उत्पाद हैं वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं, विदेशी मुद्रा विकल्प (रुपये को प्रत्यावर्तित करने वाले नहीं), विदेशी मुद्रा - रुपया विकल्प, विदेशी मुद्रा-रुपया अदला-बदली (swap), लागत न्यूनीकरण संरचना, विदेशी मुद्रा अदला-बदली, ब्याज दर अदला-बदली, कूपन अदला-बदली, ब्याज दर कैप अथवा कॉलर (खरीदियां), वायदा दर करार।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम नियम के सम्बन्ध में खुलासा किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उस अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारीकर्ता, जो कई प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाता था, की आस्तियों की गुणवत्ता के बारे में अब किसी एक ही बैंक से प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारीकर्ता को इस आशय का एक वचनपत्र देना होगा कि अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में उसके खातों को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, समेकित रकम के लिए एक ही श्रेणी निर्धारण के आधार पर कई एक श्रृंखलाओं में अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम के माध्यम से निधियां जुटाते समय लेखा-परीक्षक द्वारा प्रत्येक श्रृंखला का अलग-अलग प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है। हालांकि, जहां जारीकर्ता किसी निर्गम के लिए अलग/ नया श्रेणी-निर्धारण प्राप्त करता है, वहां इस प्रकार के निर्गम का लेखा-परीक्षक के इस प्रकार के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना आवश्यक होगा, जिसमें जारीकर्ता द्वारा निर्गम के पात्रता मानदंडों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई हो। कारपोरेट के उधार खाते को वित्तीयनकर्ता बैंक/कों अथवा संस्था/ओं द्वारा मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। कोई कारपोरेट कम्पनी अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की पात्र तब होती है, जब उसकी न्यूनतम निवल हैसियत 4 करोड़ रुपये की हो तथा बैंक द्वारा कम्पनी को कार्यशील पूंजी सीमा अथवा सावधि ऋण स्वीकृत किया गया हो।

बैंकिंग क्षेत्र की घटनाएं

बैंक फोन बैंकिंग के लिए अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ेंगे

फोन बैंकिंग को और अधिक सुरक्षित बनाने के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक से पत्र प्राप्त होने के फलस्वरूप फोन पर किए जाने वाले किसी भी लेनदेन के लिए बैंक 1 जनवरी 2011 से अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों से एक अतिरिक्त पासवर्ड की मांग करेंगे। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को स्वचालित अंत: क्रिया ध्वनि उत्तर (IVR) सेवाओं, जिसमें ग्राहकों के पास ऐसी सेवाओं के लिए एकबारगी पासवर्ड (OTP) नहीं होते, सहित टेलीफोन से किए जाने वाले किसी भी बैंकिंग लेनदेन से हर हाल में इनकार कर देना है।

निधि के भूखे बैंक 1 वर्षीय रसीद पर 9.2% ब्याज देने को तत्पर

निधि की कमी से परेशान वाणिज्यिक बैंक 10 वर्षीय सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्डों से होने वाले प्रतिलाभ से भी अधिक दर पर 1 वर्षीय धनराशि जुटा रहे हैं, इस प्रकार 'विपर्यस्त प्रतिफल वक्र' कहा जाने वाला बाज़ार विपथन निर्मित कर रहे हैं। घरेलू और कारोबारों से जमाराशियों में वृद्धि अभी तक प्रतीक्षित ही रहने के परिणामस्वरूप बैंक असंतुलन को दूर करने तथा चलनिधि की कमी पर काबू पाने के लिए थोक धनराशि जुटाने पर विवश हैं। बैंक यह मान कर चल रहे हैं कि उक्त समस्या अस्थायी है। कोई भी अधिक लागत वाली निधियों को लम्बी अवधि तक अवरुद्ध नहीं करना चाहता।

बैंकों से ऋण के उठाव में तेजी परिलक्षित

बैंकों से ऋण के उठाव में तेजी आती दिखाई देती है। 3 दिसम्बर को समाप्त पखवाड़े में ऋण का उठाव 11 नवम्बर को समाप्त पूर्ववर्ती पखवाड़े के 27,270 करोड़ रुपये की तुलना में 36,500 करोड़ रुपये के रूप में अपेक्षाकृत अधिक रहा। ऋण की मांग आधारभूत सुविधा और आवासीय खण्डों से उठती दिखाई देती है। हालांकि, बैंक जमाराशियों में पूर्ववर्ती पखवाड़े में आए 39,378 करोड़ के उछाल की तुलना में उपर्युक्त पखवाड़े में 11, 700 करोड़ रुपये की कमी आई।जमाराशियों में आई इस कमी की भरपाई बैंक विदेशी उधारों और मांग मुद्रा बाज़ार जैसे अन्य मार्गों से संसाधन जुटाते हुए कर रहे हैं।

ऋणों में जमारशियों की अपेक्षा त्वरित बढ़ोत्तरी

बैंक जमाराशियां वृद्धि की दृष्टि से ऋणों से पिछड़ती जा रही हैं। जहां ऋणों की वृद्धि 11% रही, वहीं इस वर्ष में अब तक जमाराशियों का स्तर केवल 8% ही रहा। बैंक ऋण 3 दिसम्बर के दिन बढ़ कर 35,94,559.20 करोड़ रुपये हो गए, जो पिछले पखवाड़े के स्तर से 36,499.11 करोड़ अधिक थे। यह 23% की वर्षानुवर्ष वृद्धि का भी निरूपण करता है - जो भारतीय रिज़र्व बैंक के सतोषजनक स्तर से काफी अधिक है। हालांकि, अधिक वार्षिक वृद्धि मूल प्रभाव का भी संकेत हो सकती है, क्योंकि एक वर्ष पहले ऋणों में अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि का अधिकांश आधारभूत सुविधा क्षेत्र के विविध खण्डों से तथा उसके अलावा कारपोरेट गृहों को प्रदत्त ऋणों से भी रहा, क्योंकि निवेशों में क्रमिक रूप से तेजी आ रही है। दूसरी ओर बैंक जमाराशियां 48,37,905.88 करोड़ रहीं, जो 3 दिसम्बर को समाप्त अद्यतन पखवाड़े में 11,699.6 करोड़ कम थीं। यह स्थिति भी 15% की वार्षिक वृद्धि का निरूपण करती है।

विलम्बित बासेल नियम बैंकों के लिए वरदान

बासेल बैंक विनियामकों का कहना है कि यदि पूंजीगत आवश्यकताओं से सम्बन्धित नियम विगत वर्ष के अन्त में लागू किए गए होते, तो उनके कारण वित्तीय संस्थाओं पर 602 बिलियन यूरो (797 बिलियन अमरीकी डालर) का भार पड़ता। पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने कहा है कि बैंकों को अलग से चलनिधि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक "स्थिर निधीयन" में.89 ट्रिलियन यूरो के अन्तर सहित कमियों का भी सामना करना पड़ता। समिति जुलाई माह में पूंजी एवं चलनिधि से सम्बन्धित नियमों को 2019 तक चरणबद्ध रूप में लागू करने पर सहमत हुई थी, ताकि ऋणदाताओं को भयानक मंदी से पैदा होने वाले सबसे बड़े संकट के प्रभाव से बचाया जा सके।

बैंकों ने 1,131 करोड़ उधार लिए, वाणिज्यिक पत्रों की दरें बढ़ीं

अग्रिम कर भुगतान के रूप में प्रणाली से लगभग 50,000 करोड़ रुपये बाहर चले जाने के परिणामस्वरूप बैंकों के बीच धनराशियों के लिए छीना-झपटी जारी रही। बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष पुनर्खरीद सुविधा के तहत 1.48 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 1.33 लाख करोड़ रुपये उधार लिए।

बैंककारी अधिनियम संशोधित किया जाएगा

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकार अदावीकृत रकमों से जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि सृजित करने के लिए बैंककारी विनियम अधिनियम को संशोधित करना चाहती है। 31 दिसम्बर, 2009 के दिन के भारतीय रिजडर्व बैंक के आकड़ों से यह पता चलता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) पास 1,360 करोड़ रुपये की अदावीकृत जमाराशियां थीं। भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ ही सरकार उन जमाराशियों का उपयोग ऊपर वर्णित निधि के लिए करना चाहती है, जो 10 वर्षों से अधिक की अवधि से अदावीकृत पड़ी हैं।

बढ़ती ऋण गुणवत्ता ने भारतीय स्टेट बैंक को चीन, रूस जैसे प्रतिस्पर्धियों से आगे पहुंचाया

भारतीय स्टेट बैंक के ऋणों को चूक से संरक्षित रखने की लागत सीधे 11 दिनों - वर्ष 2004 से गिरावटों की सबसे लम्बी अवधि तक कम रही, क्योंकि ऋण प्रदान करने के प्रति ऋणदाताओं की तत्परता एक सुधरती अर्थव्यवस्था का संकेत करती है। भारतीय स्टेट बैंक से सम्बन्धित ऋण चूक अदला-बदली दर में पिछले छ: महीनों में 55 आधार अंकों की गिरावट आई, जो 16 दिसम्बर को 155 रह गई। बैंक ऑफ चाइना की संविदाओं में 24 आधार अंकों की कमी आई और वह 118 रही जबकि रूस के सबसे बड़े ऋणदाता ओएओ शेरबैंक की दर 11 आधार अंक घट कर 188 रह गई। भारत के सबसे बड़े बैंक की अनुभूत ऋणपात्रता अन्य सबसे बड़े उभरते बाज़ारों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ी, क्योंकि कम्पनियों ने निर्माण परियोजनाओं के लिए उधार लेना बढ़ा दिया।

भारत में व्यापारी बैंकिंग

यद्यपि देशी बैंकर 19 वी सदी से ही मौजूद रहे हैं, भारत में निवेश बैंकिंग का वर्तमान ढांचा काफी नया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापारी बैंकिंग का पहला लाइसेंस ग्रिंडलेज बैंक को मंजूर किया गया था, जो आगे चल कर स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा अधिगृहीत किए जाने के पहले एएनजेड ग्रिंडलेज हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त लाइसेंसीकरण इसलिए किया गया था, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) केवल दो दशक बाद ही अस्तित्व में आया।

विनियामकों के कथन

बैंकों से मार्जिन घटाने हेतु कहा गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उधार दरों में कमी लाने, जमाराशियों पर अधिक ब्याज का भुगतान करने तथा समावेशी एवं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में उनकी सहायता करते हुए उनसे कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मध्यस्थता लागत घटाने का आह्वान किया है। भारतीय बैंकों के निवल

ब्याज मार्जिन (NIMs) सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों के प्रति उत्तरदायी होने के बावजूद अन्य उभरते बाज़ारों में उनके प्रतिपक्षियों की तुलना में अधिक हैं।

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की ब्याज दर की सीमा तय करने की कोई योजना नहीं

डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर किसी प्रकार का विचार नहीं कर रहा है। तथापि वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि "यह कार्यसूची में शामिल एक मुद्दा है। हम मालेगाम समिति द्वारा उसकी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इस मुद्दे पर विचार करेंगे। हमें दरों को विनियमित नहीं करना चाहिए, किन्तु इसके बजाय कोई ऐसी पद्धति विकसित करनी चाहिए, जिसके द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की ब्याज दरें थोड़ी नियंत्रित हो जाएं।"

सरकारी व्यय चलनिधि की स्थिति सहज बनाने की दृष्टि से मापक्रम में नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी सुब्बाराव ने दावा किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि की स्थिति के प्रति गंभीर रूप से जागरूक है तथा वह जब कभी आवश्यकता पड़ेगी निधि प्रवाह को सहज बनाने के लिए उपाय करेगा। उनका यह भी कहना है कि " चलनिधि की वर्तमान कमी संरचनात्मक और घर्षणात्मक , दोनों ही कारकों के कारण है। संरचनात्मक कारण यह है कि ऋण का विस्तार जमा वृद्धि की तुलना में अधिक तीव्र गति से हुआ है। स्थिति सुधर रही है, किन्तु वह चलनिधि को सहज बनाने की दृष्टि से पर्याप्त रूप से नहीं सुधरी है। घर्षणात्मक कारक है 3जी नीलामी से प्रत्याशित स्तर से अधिक की आमदनी, विर्निवेश तथा अप्रत्यक्ष कर वसूलियों से हुई आमदनी का सरकार के नकदी शेष में जमावड़ा।"

आधारभूत सुविधा परियोजनाओं का निधीयन करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बॉण्ड बाज़ार पर ध्यान केन्द्रित

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने बताया कि केन्द्रीय बैंक आधारभूत सुविधा विकास, जिसके लिए 12वीं योजना अवधि में अनुमानित रूप से 1 ट्रिलियन डालर की जरूरत होगी, के लिए एक सुदृढ़ कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किए हुए है। उन्होंने कहा कि "हम आधारभूत सुविधा परियोजनाओं का वित्तीयन करने में बैंकों की सहायता करने हेतु एक दीर्घकालिक बॉण्ड बाज़ार विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।"

विदेशी मुद्रा विनिमय

जनवरी 2011 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.78094	0.8540	1.3350		

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.78094	0.854	1.335	1.787	2.217
जीबीपी	1.50938	1.5100	1.9430	2.3390	2.6540
यूरो	1.47250	1.573	1.917	2.220	2.520
जापानी येन	1.56625	0.385	0.430	0.483	0.570
कनाडाई डालर	1.89833	1.853	0.483	2.401	2.631
आस्ट्रेलियाई डालर	5.67750	5.395	5.515	5.760	5.870

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**24 दिसम्बर 2010 के दिन**	**24 दिसम्बर 2010 के दिन**
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	**2**	**3**
कुल प्रारक्षित निधियां	13, 36, 212	295, 031
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	12, 02, 687	265,905
ख) सोना	1, 01, 857	22, 195
ग) विशेष आहरण अधिकार	22,808	5, 043
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	8, 860	1,959

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा के पुनर्मूल्यन पर विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि 911 मिलियन डालर घटी

10 दिसम्बर को समाप्त सप्ताह में देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 911 मिलियन अमरीकी डालर कम हो कर 295, 419 बिलियन डालर रह गईं। प्रारक्षित निधियों में यह गिरावट मुद्रा पुनर्मूल्यन के कारण

आई। 3 दिसम्बर को समाप्त इसके पहले वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 2, 441 बिलियन डालर की वृद्धि के साथ 295, 390 बिलियन डालर हो गई थीं।

सहकारी बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों से अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों का पालन करने के लिए कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने काले धन को वैध बनाने अथवा आतंकवादी गतिविधियों का वित्तीयन करने हेतु अपराधी तत्वों द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए सहकारी बैंकों से 'अपने ग्राहक को जानिए' (KYC) मानदंडों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि हमारे ध्यान में आया है कि ऐसे अपराधियों, जो अन्य पक्षों को शामिल करके जमा खातों तक अवैध पहुंच की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, द्वारा धोखाधड़ी की योजनाओं (फिशिंग और पहचान की चोरी) से प्राप्त राशियों को वैध बनाने के लिए मुद्रा को बेनामी रखने के तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों, धन-शोधन निवारण तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने से सम्बन्धित उनके के दायित्व का कर्तव्यपरायणता के साथ पालन किए जाने पर बेनामी खातों के परिचालन में कमी लाई जा सकती है।

3 वर्ष के लाभार्जन वाले शहरी सहकारी बैंक कारोबार संपर्की / कारोबार सुसाधक रख सकते है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि पिछले तीन वर्षों से लगातार निवल लाभ कमाने वाले शहरी सहकारी बैंक (UCBs) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उनके निदेशक मण्डल से विहित अनुमोदन की शर्त पर कारोबार संपर्की (BCs) नियुक्त करने के पात्र हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मण्डल में कम से कम दो निर्वाचित निदेशकों का समावेश हो तथा बैंक की निवल अनर्जक आस्तियां 5% से कम हों।

अर्थव्यवस्था

मुद्रास्फीति के अनुमान से सम्बन्धित जोखिम में बढ़ोत्तरी, भारतीय रिज़र्व बैंक का कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति के मोर्चे पर सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। उसकी मध्य-तिमाही की मौद्रिक नीति की समीक्षा में कहा गया है कि मार्च 2011 तक 5.5% की मुद्रास्फीति से सम्बन्धित अनुमान से जुड़ा जोखिम चिरस्थायी घरेलू मांग और जिंसों की वैश्विक कीमतों के अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण अधिक है। यद्यपि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित मुद्रास्फीति के अक्तूबर के 8.58% के स्तर से घट कर नवम्बर में 7.5% पर आ जाने के

परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में कमी आई है, तथापि खाद्य मूल्यों में गिरावट की गति व्यापक तौर पर संरचनात्मक कारकों के कारण अपेक्षा से धीमी रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि "इसमें यह जोखिम निहित है कि जिंसों की बढ़ती अन्तरराष्ट्रीय कीमतें घरेलू मुद्रास्फीति तक फैल जाएंगी। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र के मामले में घरेलू निविष्टि की बढ़ती लागतें समग्र मांग के दबाव के साथ मिल कर घरेलू मुद्रास्फीति तक विस्तारित हो सकती हैं।"

चलनिधि की स्थिति सहज बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक 12,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी जारी करेगा

चलिनिधि को सुगम बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुले बाज़ार के परिचालनों की घोषणा की है, जिनके माध्यम से वह कुल 12,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ये प्रतिभूतियां 15 दिसम्बर को बहुविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए नीलामी के माध्यम से खरीदी गई थीं। नये खुले बाज़ार के परिचालन में वे 3 सरकारी प्रतिभूतियां, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वापस खरीदी जाएंगी, 7.02% वाली सरकारी प्रतिभूति 2016, 7.99% वाली सरकारी प्रतिभूति 2017 और 8.13% वाली सरकारी प्रतिभूति 2022 हैं। इसी प्रकार के हाल ही के एक मामले में केन्द्रीय बैंक ने प्रणाली में 10,000 करोड़ रुपये की चलनिधि उतारी थी। इसके पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह कहा था कि वह जब कभी आवश्यक समझा जाएगा प्रणाली में चलनिधि लाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। इसके अतिरिक्त चलनिधि की कमी से निपटने में बैंकों की सहायता करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अस्थायी उपाय के रूप में उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों अथवा सांविधिक चलनिधि अनुपात के रूप में अपनी निवल मांग एवं सावधि देयताओं के केवल 23% अंश धारित करने की अनुमति प्रदान की थी। 29 अक्तूबर, 2010 से बैंक 24% का सांविधिक चलनिधि अनुपात रखते रहे हैं। इसके अलावा, बैंक दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) पटल का उपयोग इसके पूर्व घोषित 16 दिसम्बर, 2010 तक की बजाय 28 जनवरी 2011 तक कर सकते हैं। कुल मिला कर 2% की निवल मांग एवं सावधि देयता की रकम लगभग 95,000 करोड़ रुपये होगी। यह रकम 1 लाख रुपये की उस रकम के करीब है, जो बैंक उधार लेते रहे हैं।

मूल्य स्थिरता केन्द्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन ने इस बात पर बल देते हुए कि विनिमय दरों को स्थिर रखने के लिए मौद्रिक प्राधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप अपवादात्मक मामले होने चाहिए, कहा कि मूल्य स्थिरता विकासशील देशों के केन्द्रीय बैंकों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

पारस्परिक निधियां

पारस्परिक निधि में सभी निवेशों के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) अनिवार्य

पारस्परिक निधियों के नये और मौजूदा सभी निवेशकों के लिए अब 1 जनवरी, 2011 से उनके स्थायी खाता संख्या (PAN) से सम्बन्धित विवरण अनिवार्य रूप से देना आवश्यक होगा, उनके निवेश का आकार चाहे जितना भी क्यों न हो। अब तक निवासी वैयक्तिक निवेशकों को स्थायी खाता संख्या के विवरण दिए बिना ही 50,000 रुपये तक का निवेश करने की अनुमति थी।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं दबाव में

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं कुछ दबाव में हैं और बैंकों को उन्हें उधार देना न्यायोचित ठहराने में कठिनाई हो रही है, यह कहना है भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का, जिन्होंने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को भारत की समावेशी रणनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक बताया है। डॉ. गोकर्ण का कहना है कि "इस समुदाय को ऐसे तरीकों से परिचालन करना होगा जो केन्द्रीय बैंक की समग्र समावेशी कार्यसूची से सुसंगत हों।" वह इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि "सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जिस अंतिम मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हुई हैं, वहां तक औपचारिक क्षेत्र नहीं पहुंच पाया है।"

आन्ध्र प्रदेश ने सूक्ष्मवित्त विधेयक पारित किया

सुक्ष्म वित्त संस्थाओं को विनियमित करने के लिए लाए गए आन्ध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संस्था ((साहूकारी का विनियमन) विधेयक 2010 पर विधानसभा में बहस हुई तथा वह किसी संशोधन के बिना पारित हो गया। जहां सूक्ष्म वित्त संस्थओं के पैरोकार संगठन, सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क (MFIN) ने अपनी चिंता व्यक्त की थी और साप्ताहिक वसूली की मांग की थी, वहीं सरकार ने मासिक वसूली को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, जहां सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क किसी सार्वजनिक स्थल को वसूली केन्द्र बनाए जाने का इच्छुक था, वहीं सरकार पंचायत कार्यालय को एकमात्र वसूली स्थल बनाना चाहती थी। तीसरे, सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क केन्द्रीकृत पंजीकरण प्रणाली चाहता था, जबकि सरकार जिलों में स्थित सभी शाखाओं को पंजीकृत कराए जाने की पक्षधर थी।

अन्तरराष्ट्रीय समाचार

स्विस बैंक अवैध धन के लिए सुरक्षित स्थल नहीं

अंतरराष्ट्रीय संप्रेषण और स्विस बैंकर संघ (SBA) के प्रधान श्री जेम्स नैसन का दावा है कि "स्विस बैंक धन छिपाने का कारबार नहीं करते। उन्ह धन कहां से आया इसका सत्यापन करने के लिए

कुछेक विहित कर्तव्यपरायणता सम्बन्धी दायित्व निभाने पड़ते हैं। आज स्विटज़रलैंड वह अंतिम स्थान है, जहां अपराधी धन को छिपाने और उसे वैध बनाने का प्रयास कर सकें।" स्विस बैंकर संघ वह मुख्य व्यावसायिक व्यापारी संघ है, जो स्विटज़रलैंड और विदेशों में स्विस बैंकिंग उद्योग की ओर से पैरवी करता है। यह एक ऐसा स्व-विनियामक निकाय है, जिसके स्विटज़रलैंड के लगभग सभी बैंक सदस्य हैं। श्री नैसन स्विस बैंकिंग के साथ जुड़े कुछेक प्रचलित मिथकों को यह कहते हुए खंडित कर देते हैं कि "आप किसी स्विस बैंक में कोई बेनामी खाता नहीं रख सकते। वे कानून द्वारा निषिद्ध हैं। बैंक आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं। बैंक इस बात का पता लगाने के लिए भी बाध्य हैं कि आस्तियों का हितकारी स्वामी कौन है।"

घाटा कम करने के लिए ब्रिटिश बैंकों पर अधिक कर

यू. के. सरकार आगामी चार वर्षों में लगभग 9 बिलियन पौण्ड (14 बिलियन डालर) जुटाते हुए बैंकों के तुलन पत्रों पर इसके पहले प्रस्तावित स्तर से अधिक कर लगाएगी। 1 जनवरी से सरकार ने जून 2010 में घोषित 0.04% की बजाय 0.05% प्रभारित करना आरंभ कर दिया है।

चीन ने आरक्षित निधियों में वृद्धि को 6 शीर्ष बैंकों तक विस्तारित किया

चीन के केन्द्रीय बैंक ने देश के छ: सबसे बड़े ऋणदाताओं से कहा है कि मुद्रास्फीति को रोकने के अद्यतन उपाय के रूप में अपेक्षित आरक्षित निधियों में विशेष वृद्धि को विस्तारित किया जाएगा। इस मुहिम से नकदी के एक ऐसे खंड, जिसे बैंक अन्यथा उधार दे सकते थे, को अवरुद्ध करते हुए उस चलनिधि को अवशोषित करने में सहायता मिलेगी, जिसने नवम्बर माह में मुद्रास्फीति को 28 माह की अवधि के शिखर अर्थात् 5.1% के अपेक्षा से अधिक पर पहुंचा दिया।

उद्योग में उच्छलन के फलस्वरूप अमरीकी पुनरुत्थान में गति आई

जुलाई से अब तक के अपने सबसे बड़े अभिलाभ में नवम्बर में औद्योगिक उत्पादनं प्रतिस्पंदित हुआ, जिससे 4थी तिमाही के दौरान पुनरुत्थान की गति में तेजी परिलक्षित हुई। हालांकि, पिछले माह में उपभोक्ता मूल्यों में अत्यल्प वृद्धि हुई, जिससे अर्थव्यवस्था में अभ भी प्रचुर मंदी की याद ताज़ा हो जाती है तथा यह निश्चितप्राय लगता है कि फेडरल रिज़र्व अर्थव्यवस्था को और अधिक सहायता पहुंचाने के लिए 600 बिलियन डालर के सरकारी बॉण्डों की खरीद वाले विवादास्पद कार्यक्रम को पूरा करेगा।

नयी नियुक्तियां

श्री वी. कन्नन ने ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) के महा प्रबन्धक थे।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ किया गया	उद्देश्य
इलाहाबाद बैंक	ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड	वैयक्तिक उपयोग के लिए वाहन की खरीद हेतु बैंक के वित्तीयन को बढ़ावा देना
येस बैंक	नेशनल कोलैटरल मैनेज़मेंट सर्विसेज लिमिटेड	उद्योगों, व्यापारियों और किसानों की पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं के वित्तीयन में उनकी सहायता करने हेतु संपार्श्विकों के प्रबन्धन एवं भण्डारण सेवाओं के लिए
मेटलाइफ	यूनाइटेड बैंक के साथ समझौता ज्ञापन	यूनाइटेड बैंक के सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यम ग्राहकों को ऋण बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु
पंजाब नैशनल बैंक	अतुल ऑटो	पूरे देश में अतुल ऑटो के सभी उत्पादों को वाहन वित्तीयन उपलब्ध कराने हेतु
ऐक्सिस बैंक	आइडिया सेलुलर के साथ समझौता ज्ञपान	अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से ऐक्सिस बैंक के वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आइडिया ऐक्सिस बैंक का कारबार संपर्की होगा
यूनियन बैंक	भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन	भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को दूरसंचार सेवाओं का पूर्ण वर्णक्रम उपलब्ध कराने में समर्थ बनाने हेतु यूनियन बैंक ने अधिमानी भागीदार के रूप में गंठजोड़ किया है
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	चाइना विकास बैंक के साथ समझौथा ज्ञापन	दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश को सहायता प्रदान करने हेतु
धनलक्ष्मी बैंक	दोहा बैंक	उसके अनिवासी भारतीय ग्राहकों को ऑनलाइन निधि विप्रेषण सुविधा प्रदान करने हेतु
कॉस्मॉस सहकारी बैंक	वएस्टर्न यूनियन	ग्राहकों को 2,500 डालर या उसके समकक्ष तक की वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु

पूंजी बाज़ार

सेबी को निवेश बैंकों द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव देने में विगत प्रदर्शन दर्शाए जाने की दरकार

निवेशकों को बैंकों द्वारा ग्राहकों का चयन करने और मूल्य-निर्धारण में बरती जाने वाली उचित कर्तव्यपरायणता की त्वरित अन्तर्दृष्टि उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के प्रलेखों में निवेश बैंकों द्वारा शेयर बिक्री व्यवस्था के 3 वर्ष के कार्य-निष्पादन का प्रकाशन अनिवार्य किया जा सकता है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के प्रलेखों में विगत शेयर बिक्री का पिछला रिकार्ड निवेशकों के लिए ऐसे बैंकरों द्वारा प्रबन्धित शेयर निर्गमों से बचने में सहायक हो सकता है, जिनमें

शेयरों की कीमतों का कार्य-निष्पादन घटिया रहा हो अथवा कारपोरेट अभिशासन के मुद्दे शेष रहे हों। यह प्रस्तावित है कि सभी व्यापारी बैंकरों को पिछले रिकार्ड प्रकट करने के निर्देश दिए जाएं।

जिंस (पण्य) बाज़ार

एमसीएक्स बाज़ार व्युत्पन्नियां विकसित करेगा

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) ताइवान के फ्यूचर एक्सचेंज (TAIFEX) के साथ मिलकर सूचना, प्रौद्योगिकी तथा पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी करते हुए दोनों ही देशों में जिंस व्युत्पन्नी बाज़ारों का विकास करेगा। ताइवान के फ्यूचर एक्सचेंज (TAIFEX) के प्रबन्ध निदेशक श्री लैमन रुटेन यह दावा करते हैं कि समझौता ज्ञापन एक-दूसरे के बाज़ारों को समझने तथा विशेषज्ञता एवं उत्तम परंपराओं में हिस्सेदारी करने का अवसर प्रदान करेगा। एमसीएक्स बुलियन, बेस मेटल, ऊर्जा, कृषि एवं अन्य जिंसों में जिंस वायदा संविदाएं (Commodity futures contracts) उपलब्ध कराता है, जबकि ताइवान का फ्यूचर एक्सचेंज (TAIFEX) इक्विटी और जिंस व्युत्पन्नी दोनों ही प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराता है।

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक की स्थापना

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक की स्थापना 17 मई, 1930 को की गई थी। अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक विश्व का प्राचीनतम अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है तथा वह अन्तरराष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक सहयोग का मुख्य केन्द्र बना हुआ है।

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक की स्थापना यंग प्लान (1930) के संदर्भ में की गई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्सेल्स की संधि द्वारा जर्मनी पर लगाई गई क्षतिपूर्ति के भुगतानों के मुद्दे से सम्बन्धित था। नये बैंक द्वारा उन कार्यों; क्षतिपूर्ति के रूप में देय वार्षिकियों की वसूली, प्रशासन एवं वितरण; का दायित्व संभाला जाना था जो इसके पहले बर्लिन में स्थित एजेन्ट जनरल द्वारा निष्पादित किए जाते थे। बैंक का नाम इसी मौलिक भूमिका से ग्रहण किया गया है। अन्तरराघ्ट्रीय निपटान बैंक की रचना इसलिए भी की गई थी कि वह डावेस और यंग ऋणों (क्षतिपूर्तियों का वित्तीयन करने हेतु जारी किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय ऋणों) के लिए एक न्यासी के रूप में कार्य करे तथा सामान्य रूप में केन्द्रीय बैंक से सहयोग को बढ़ावा दे।

क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित मुद्दा शीघ्र ही समाप्त हो गया तथा बैंक के कार्यकलापों को पूर्णत: केन्द्रीय बैंकों के बीच सहयोग तथा अधिकाधिक रूप से मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता के प्रयास में संलग्न अन्य

एजेन्सियों पर संकेन्द्रित हो गया।

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक (**BIS**) एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन है जो अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है तथा केन्द्रीय बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है।

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक इस अधिदेश को निम्नलिखित रूप में कार्य करते हुए पूरा करता है :

- केन्द्रीय बैंकों के बीच और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय समुदाय में विचार-विमर्श और नीतिगत विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए एक मंच
- आर्थिक एवं मौद्रिक अनुसंधान के लिए एक केन्द्र
- केन्द्रीय बैंकों के लिए उनके वित्तीय लेनदेनों में एक मुख्य प्रतिपक्ष (counterparty)
- अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय परिचालनों के सम्बन्ध में एजेन्ट अथवा न्यासी

इसका प्रधान कार्यालय बासेल, स्विटज़रलैंड में है तथा चीनी जन गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग में और मैक्सिको नगर में दो प्रतिनिधि कार्यालय हैं।

चूंकि इसके ग्राहक केन्द्रीय बैंक तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठन हैं, अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक निजी व्यक्तियों और कारपोरेट कम्पनियों से जमाराशियां नहीं स्वीकार करता अथवा उन्हें वित्तीय सेवाएं नहीं प्रदान करता। अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक कपटपूर्ण योजनाओं के विरुद्ध सख्ती से सूचना (जानकारी) देता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात

किसी कम्पनी के लिए उत्पादन की अगली इकाई सृजित करने के लिए आवश्यक निवेश पूंजी की न्यूनतम रकम का निर्धारण करने वाला माप। कुल मिलाकर अपेक्षाकृत अधिक वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात को वरीयता नहीं दी जाती, क्योंकि इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि कम्पनी का उत्पादन अपर्याप्त है। इस माप का उपयोग मुख्यतया किसी देश की उत्पादन कुशलता का स्तर निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है :

$$\text{वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात} = \frac{\text{वार्षिक निवेश}}{\text{सकल आरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि}}$$

शब्दावली

विदेशी मुद्रा अदला-बदली

दो भिन्न -भिन्न मुद्राओं में मूल्यवर्गित ब्याजगत भुगतानों तथा ऋणों से सम्बन्धित मूलधन का विनिमय करने हेतु दो पक्षकारों के बीच हुआ करार। विदेशी मुद्रा अदला-बदली में किसी ऋण के एक मुद्रा में ब्याजगत भुगतानों और मूलधन की किसी अलग मुद्रा में समान मूल्य वाले ऋण एवं ब्याजगत भुगतानों से विनिमय किया जाएगा।

विपर्यस्त प्रतिफल वक्रं

एक ऐसा ब्याज दर वातावरण, जिसमें दीर्घकालिक ऋण लिखतों का प्रतिफल उसी ऋण गुणवत्ता वाले अल्पकालिक ऋण लिखतों से कम होता है। इस प्रकार का प्रतिफल वक्र तीन मुख्य प्रकार वाले वक्रों में सर्वाधिक दुष्प्राप्य होता है तथा उसे आर्थिक मंदी का पूर्वानुमानकर्ता माना जाता है। आंशिक विपर्यय उस समय होता है जब अल्पकालिक खजानों (5 या 10 वर्षों वाले) में से केवल कुछेक के ही प्रतिफल 30 वर्षीय खजानों वालों से अधिक होते हैं। विपर्यस्त प्रतिफल वक्र को कभी-कभी "नकारात्मक प्रतिफल वक्र" कहा जाता है।

संस्थान समाचार

उन्नत धन-संपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम

वित्तीय परामर्श में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को आगामी परीक्षा से उन्नत धन-संपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम का नया नाम दिया गया है।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या एमआर/ तक/ डब्ल्यूपीपी-15 /
  दक्षिण / 2010 - 12 मुंबई

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

कारबार संपर्की / कारबार सुसाधक से सम्बन्धित पुस्तक

मराठी संस्करण :

"कारबार संपर्की / कारबार सुसाधक के माध्यम से समावेशी विकास" पुस्तक के मराठी संस्करण का विमोचन 23 दिसम्बर, 2010 को मुंबई में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के. भट्टाचार्य द्वारा किया गया।

बंगाली संस्करण :

"कारबार संपर्की / कारबार सुसाधक के माध्यम से समावेशी विकास" पुस्तक के बंगाली संस्करण का विमोचन 23 दिसम्बर, 2010 को कोलकाता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ. असीम कुमार दासगुप्ता द्वारा किया गया।

परियोजना वित्त में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

संस्थान आईएफएमआर, चेन्नै के सहयोग से परियोजना प्रबन्धन में 13वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। बैच के लिए कैम्पस प्रशिक्षण का शुभारंभ 21 फरवरी से 26 फरवरी 2011 तक हो रहा है।

बाज़ार की खबरें

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

20800
20500
20200
20000
19800
19600
19400
19200
19000
18800
18600
01/12/10 02/12/10 08/12/10 09/12/10 10/12/10 13/12/10 14 /12/10 15/12/10
16/12/10 21/12/10 23/12/10 24/12/10 29/12/10 30/12/10 31/12/10

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- अमरीकी डालर श्रेणीबद्ध रहा।
- रुपया 44.81 और 45.70 के बीच घटता-बढ़ता रहा।
- माह के दौरान रुपये के मूल्य में 1.95 % की वृद्धि हुई।
- स्टर्लिंग अनियमित बना रहा।
- स्टर्लिंग 3.06% बढ़ा।
- यूरो के समक्ष रुपये में 0.47 % का मूल्यह्रास हुआ।

भारित औसत मांग दरें

01/12/10 03/12/10 04/12/10 06/12/10 09/12/10 11/12/10 13/12/10 16/12/10 20/12/10 27/12/10 29/12/10 31/12/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, दिसम्बर, 2010
मांग दरें 5.85 और 6.97 के बीच मंडराती रहीं।
चलनिधि की स्थिति सहज तथा दरें श्रेणीबद्ध रहीं।
20 दिसम्बर को 23 वीं तक चलनिधि की मामूली कमी।

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड,
मुंबई - 400 005

टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093

तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जनवरी, 2011